

66 गिरफ्तारियों में 45 गैर-श्रमिक

आगजनी-भड़काने में बाहरी तत्वों की भूमिका

साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है

लखनऊ/नोएडा, 16 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के नोएडा में हालिया श्रमिक आंदोलन के दौरान फैली हिंसा और अराजकता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह महज श्रमिक असंतोष का मामला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें बाहरी तत्वों की सक्रिय भूमिका रही। सूत्रों के अनुसार, अब तक हुई 66



गिरफ्तारियों में से 45 लोग ऐसे पाए गए हैं, जो वास्तविक श्रमिक नहीं हैं। आगजनी की घटनाओं में चिन्हित 17 लोगों में से 11 को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 8 गैर-श्रमिक हैं। वहीं, भड़काने के आरोप में चिन्हित 32 में से 19 को हिरासत में लिया गया है। इसके अतिरिक्त 34 ऐसे लोगों को भी

पकड़ा गया है, जो श्रमिक न होते हुए भी प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल बिगाड़ने को कोशिश कर रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक, साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है, जिनके कुछ संगठित नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।

मामले में कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडलस और बाहरी राज्यों से आए लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सूत्रों का दावा है कि नोएडा के औद्योगिक ढांचे को प्रभावित करने के लिए व्यापक स्तर पर योजना बनाई गई थी। हिंसा के दौरान आगजनी, पथराव और उकसावे की घटनाओं में शामिल कई लोग स्थानीय श्रमिक नहीं थे, बल्कि बाहर से आए तत्व थे, जिनका उद्देश्य औद्योगिक माहौल को अस्थिर करना था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल सख्त कदम उठाए।

महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव 12 मई को नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटों के लिए द्वैवाचिक चुनाव 12 मई को कराये जाने की पुष्टि की। घोषणा की इन सीटों के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार इन सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना 23 अप्रैल को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र 30 अप्रैल तक भर जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 2 मई को की जाएगी और नाम 4 मई तक कागज पर लिखे जा सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मतदान 12 मई को सुबह 9-00 बजे से शाम 4-00 तक कराया जाएगा। मतों की गिनती मतदान के बाद उसी दिन कराई जाएगी और चुनाव प्रक्रिया 13 मई से पहले संपन्न कर ली जाएगी।

मीट एंड अवॉर्ड समारोह के आयोजकों से धामी ने की भेंट आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई

देहरादून, 16 अप्रैल. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को उनके आवास में इंडिया डिजिटल इंपॉवरमेंट मीट एंड अवॉर्ड समारोह के आयोजकों ने शिष्टाचार भेंट की और आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

धामी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन वर्तमान समय की आवश्यकता हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और साईंस से जुड़े विविध विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कांफ्रेंस से प्राप्त निष्कर्ष और सुझाव भविष्य में सकारात्मक परिणाम देने के



साथ-साथ राज्य और देश के डिजिटल विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है।

राज्य में प्रतिवर्ष छह करोड़ से अधिक श्रद्धालु एवं पर्यटक विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के कारण अनेक आकर्षक डेस्टिनेशन उपलब्ध हैं। राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण है, जिससे फिल्म उद्योग के क्षेत्र में व्यापक बदलाव संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक निवेश के लिए भी राज्य में बेहतर अवसर उपलब्ध हैं, जिन्हें और विकसित करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को वैश्व डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के सुरम्य स्थल और आधुनिक सुविधाएं इसे डेस्टिनेशन वैडिंग के लिए उपयुक्त बनाती हैं। सरकार इस दिशा में आवश्यक आधारभूत संरचना और सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़

बैंक कर्मचारी सहित 3 लोग हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली 16 अप्रैल. दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर के तहत एक बड़े साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक बैंक कर्मचारी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह रैकेट म्यूल् बैंक खातों के जरिए संचालित होता था। म्यूल् खाते, ऐसे खाते होते हैं जिन्हें अपराधी फर्जी ढंग से खुलवाते हैं और ठगी की रकम उसमें रखते हैं। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) राजीव कुमार ने बताया कि यह मामला एक ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत के बाद प्रकाश में आया,

जिसमें एक पीड़ित के खाते से 10,000 रुपये निकाले गए थे। जांच के दौरान मयूर विहार स्थित एक निजी बैंक शाखा में एक संदिग्ध म्यूल् खाते की पहचान हुई। यह खाता साइबर धोखाधड़ी की कई अन्य शिकायतों से भी जुड़ा पाया गया। पुलिस टीम ने केंवाईसी दस्तावेजों और लेनदेन के पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद सबसे पहले खाताधारक शौकीन को पकड़ा। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने अपने भतीजे शाहरुख उर्फ जोजो के कहने पर यह खाता खोला था। इसके बाद शाहरुख को गिरफ्तार किया गया, जिसने बैंक कर्मचारी की सल्लसता का खुलासा किया।

लीशर वैली में सैपल फ्लैट का अनावरण एनबीसीसी ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया कार्यक्रम का आयोजन

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. एनबीसीसी ने लीशर वैली, ग्रेटर नोएडा में भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर की जयंती को श्रद्धापूर्वक मनाया।

जयंती के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान के निर्माता और समानता, न्याय तथा सशक्तिकरण के समर्थक को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिनके आदर्श आज भी राष्ट्र की प्रगति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। राष्ट्र निर्माण तथा सामाजिक न्याय में उनके अद्वितीय योगदान को याद



करते हुए बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में आर. वेंकटरमण, भारत के महान्यायाधीश एवं लर्नेड कोर्ट

रिसीवर (आग्रपाली परियोजनाएं), डॉ. केपी महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी तथा डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य)

की गरिमायुगी उपस्थिति रही। समारोह के दौरान वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य गण्यमानजन भी उपस्थित रहे। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, एनबीसीसी ने लीशर वैली एफएआर परियोजनाओं, ग्रेटर नोएडा में सैपल फ्लैट का उद्घाटन भी किया, जो चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति को प्रदर्शित करता है। सराहना और समावेशिता की भावना को दर्शाते हुए, इस कार्यक्रम के दौरान श्रमजीवियों और उनके बच्चों को सम्मानित किया गया।

अनिल अंबानी को सुको से राहत नहीं

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी की उस याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने बोम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बैंकों को उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी।

यह मामला बोम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले से संबंधित है जिसमें दो बैंकों को अनिल अंबानी के लोन खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने दिसंबर 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें अनिल अंबानी को अंतरिम राहत दी गई थी।



मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने टिप्पणी की कि बोम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का आदेश उस मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जिसका फैसला होना बाकी है और उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया।

इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर पर राजी: ट्रम्प

वॉशिंगटन, 16 अप्रैल. ट्रम्प ने ट्विटर सोशल पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जिसके बाद यह सहमति बनी। उन्होंने बताया कि

वह नेतन्याहू और जोसेफ औन को वॉशिंगटन में बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हफ्ते वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई थी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी

शामिल थे। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन केन को निर्देश दिए हैं कि वे दोनों देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति सुनिश्चित करने की दिशा में काम

करें। इससे पहले लेबनानी राष्ट्रपति ने ट्रम्प से फोन पर बातचीत में सीजफायर के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद किया। अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीजफायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं।

आज का इतिहास

- 1799 - श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी शुरू. 4 मई को टीपू सुल्तान की मौत के साथ इस्लाम अंत हुआ।
- 1941 - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
- 1946 - सीरिया ने फ्रांस से आजादी मिलने की घोषणा की।
- 1947 - श्रीलंका के महानतम खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन का जन्म।
- 1971 - मिस्र, लीबिया और सीरिया ने मिल कर यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया।

एलपीजी की जमाखोरी के खिलाफ 2500 छापे

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बीच रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एलपीजी की जमाखोरी और काला बाजारी के खिलाफ तेजी तथा मजबूती के साथ अभियान चलाया जा रहा है और बुधवार को देश भर में 2500 से अधिक छापे मारे गये।

पश्चिम एशिया संकट के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुवार को आयोजित अंतर मंत्रालय वीरिफिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि खान मंत्रालय कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला में संभावित बाधाओं से निपटने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। अधिकारियों ने



बताया कि बुधवार को देश भर में 2,500 से अधिक छापे मारे गए, जबकि तेल विपणन कंपनियों ने 238 एलपीजी वितरण पर दंड लगाया और अनिश्चितताओं के कारण 63 को निलंबित किया। खान मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय ने हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत की है और अप्रैल के प्रारंभ में एल्युमिनियम

उत्पादकों, तांबा उद्योग प्रतिनिधियों और प्रमुख उद्योग संगठनों जैसे एफआईएमआई, फिक्की, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई और एसोचैम के साथ तीन महत्वपूर्ण बैठकों की। इन बैठकों से प्राप्त सुझावों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है।

भाजपा आई तो माफिया झाड़ू लगाएंगे : योगी

'न दंगा, न कर्फ्यू': योगी ने गिनाए यूपी के मॉडल, योगी बोले- हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे

चुनावी रण में योगी: बंगाल में कानून-व्यवस्था मुद्दा



उन्होंने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के 'डबल इंजन सरकार' मॉडल को उदाहरण के तौर पर पेश किया और कहा कि वहां अब न दंगा होता है, न कर्फ्यू लगता है। योगी ने यह भी कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक पहचान को गारंटी दे मुद्दा बनाया। योगी ने

बयान ने बंगाल की सियासत को और गर्म कर दिया है, जहां पहले से ही भाजपा और टीएमसी के सरकार बनने पर प्रदेश में माफिया और गुंडाराज खत्म हो जाएगा।

सफल अपील पर चुनाव आयोग जारी करे पूरक सूची: सुको

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसने चुनावी प्रक्रिया और मताधिकार के सवाल पर स्पष्टता ला दी है। अदालत ने साफ कहा कि केवल अपील लंबित होने के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह फैसला उन याचिकाओं पर आया, जिनमें मतदाता सूची से हटाए गए लोगों ने अंतरिम राहत के रूप में वोट डालने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को यह निर्देश भी दिया कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण मतदान से पहले अपीलों का निपटारा कर देते हैं, तो सफल आवेदकों को पूरक मतदाता सूची में शामिल किया जाए। इससे ऐसे लोगों के लिए मतदान का रास्ता खुला रहेगा, जिनकी अपील समय पर स्वीकार हो जाती है। यह फैसला चुनावी पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यह मामला 'विशेष गहन संशोधन' प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसके तहत मतदाता सूची की व्यापक जांच की गई थी।



ममता बनर्जी बोलीं- धैर्य का मिला फल, न्याय हुआ कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका पर गर्व जताया है। उन्होंने पहले ही लोगों से धैर्य रखने की अपील की थी और अब अदालत के आदेश से यह साफ हो गया है कि जिन लोगों ने अपील की है, उन्हें न्याय मिलेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल तक फैसले सुनाएंगे और उसके बाद सलामीटो वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे पात्र लोगों को मतदान का अधिकार मिल सकेगा। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र और न्याय की जीत करार दिया।

हरिवंश को उप सभापति चुना जाना तय

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हरिवंश का उच्च सदन के उप सभापति के पद पर निर्विरोध चुना जाना तय है क्योंकि इस चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त चुकी है और विपक्ष की ओर से किसी ने नामांकन नहीं किया है। हरिवंश ने उच्च सदन के उप

सभापति के लिए शुक्रवार को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन किया है और उनके नामांकन के समर्थन में पांच प्रस्ताव दिये गये हैं। चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि गुरुवार को दोपहर बारह बजे तक थी। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर संसदीय

परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार निर्धारित समय तक विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है इसलिए श्री हरिवंश का उपसभापति चुना



जाना तय है। इस तरह हरिवंश लगातार दूसरी बार उप सभापति चुने जायेंगे।

नितिन नवीन समेत 16 सदस्यों ने राज्यसभा में ली शपथ



नई दिल्ली, 16 अप्रैल. राज्यसभा में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन समेत 16 नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली। संसद के मौजूदा बजट सत्र में तीन दिन की विशेष बैठक के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलायी गयी। शपथ लेने वालों में असम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन सदस्य तेराश गोवाला, जोगेन मोहन और प्रमोद बोरा शामिल हैं। बिहार से भाजपा के नितिन नवीन और शिवेश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के राम नाथ ठाकुर तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने सदस्यता की शपथ ली।

नव भारत

श्री प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी नवभारत चैरीटेबल ट्रस्ट द्वारा छात्र छात्राएँ एवं सभी आयु वर्ग के लिए फ्री कम्प्यूटर प्रशिक्षण आवेदन करें

मो. 7772991010 इस WhatsApp No.

या नवभारत प्रेस में जमा करें समय 10 से 5 के बीच में पता- 3 इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग जोन 1 एम.पी. नगर भोपाल

विजय का घोषणापत्र: महिलाओं-किसानों के लिए तोहफे

चेन्नई. तमिलनाडु की राजनीति में नई एंटी करने वाले अभिनेता-से-राजनेता विजय ने अपनी पार्टी तमिलनाडु वेनी कडमम का चुनावी घोषणापत्र जारी कर सियासी हलचल तेज कर दी है। 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जारी इस घोषणापत्र में महिलाओं, किसानों, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को केंद्र में रखते हुए कई बड़े और आकर्षक वादे किए गए हैं। विजय ने खासतौर पर महिलाओं को साधने के लिए हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता और साल में छह मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, जो सीधे तौर पर परिवारों के खर्च को कम करने का प्रयास माना जा रहा है। इसके अलावा, किसानों के लिए कर्ज माफ़ी और बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे ऐलान भी किए गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय ने अपने चुनावी घोषणापत्र के जरिए राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।



अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें चुनाव की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चल रही विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच वह चुनाव आयोग के इन फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि चुनावों के दौरान ऐसे तबादले सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं और यह कई राज्यों में होते हैं। चुनाव आयोग के राष्ट्रव्यापी आंकड़ों की जांच करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि आंकड़ों से पता चला कि अन्य राज्यों में स्थानांतरित किए गए अधिकारियों की संख्या पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित अधिकारियों की संख्या से कहीं अधिक थी।